

प्रधक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड पौड़ी.

सेवा में

1. आचार्य,
प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र,
रुद्रपुर, हवालबाग, हरिद्वार, पौड़ी, गोपेश्वर, शंकरपुर, थरकोट एवं हल्द्वानी.
2. सहायक आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी.

पत्रांक 25/8 / 5-बजट / प्र.प्र.के. / 2011-12 दिनांक मई ०३ 2011

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि का आवंटन.

महोदय,

सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 677/XI/2011 / 56 (32) 2011 / दिनांक 11.4.2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्यय में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आयोजनेतर पक्ष की बचनबद्ध मदों हेतु ₹ 5,15,01,000.00 (रूपये पांच करोड़ पन्द्रह लाख एक हजार मात्र) की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 5,12,44,500.00 (रूपये पांच करोड़ बारह लाख चवालिस हजार पांच सौ मात्र) का आवंटन संलग्न परिशिष्ट एक के अनुसार संस्थानों को किया जा रहा है। यह धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में यह आवंटन प्रथम बार किया जा रहा है।

- (1) बजट प्राविधान के किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा तक ही व्यय किये जाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में व्यय न किया जाय और न ही पुर्णविनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में काई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
- (2) आयोजनागत पक्ष की नई योजनाओं के प्रस्ताव पर स्वीकृति परिव्यय व बजट प्राविधान को दृष्टिगत करते हुए नियोजन/वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी।
- (3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्राक्योरमेंट रूल्स, 2008 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (4) निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (5) निर्माण कार्य हेतु पूरे वर्ष के सम्भावित व्यय की फेजिंग कर के कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करेंगे तथा लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण किया जाना भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
- (6) प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्र सहायतित/वाहय सहायतित योजनाओं में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी। केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली अवशेष धनराशि का विवरण भी उपलब्ध कराया जाय।
- (7) बिना वित्त विभाग की सहमति के किसी भी स्तर से किसी भी प्रकार के पुर्णविनियोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। पुर्णविनियोग का प्रस्ताव बजट मैनुअल के पैरा 151 के अन्तर्गत परिक्षणोपरान्त प्रस्तुत

कमश: . . . 2 . . .

पत्रांक 258 / 5-बजट-(अ)सामुदायिक वि०/2011-12, दिनांक उक्त.

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

1. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर, अल्मोड़, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़ एवं नैनीताल .(पंजीकृत)
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून.
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस सी-१/१०५ इन्दिरा नगर, देहरादून.
4. मुख्य विकास अधिकारी, उधमसिंह नगर, अल्मोड़, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़ एवं नैनीताल .
5. सहायक आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी.
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा उत्तराखण्ड.
7. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून.
8. अपर सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. अपर सचिव, वित्त (आय-व्ययक) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
10. अपर आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन)/सहायक सम्रेक्षण अधिकारी ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड पौड़ी.
11. गार्ड फाइल.

संलग्न-उक्त/

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
ग्राम्य विकास.

२५८ /५-बजे/ २०११-

2011

卷二